क्या 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020' भारतीय किसानों के लिए एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा?

"एक अध्यादेश जो ऐसा इको पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करेगा जहाँ किसान और व्यापारी किसानों के उपज की बिक्री और खरीद के संबंध में चुनने की स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है। यह अध्यादेश प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से पारिश्रमिक कीमतों की सुविधा प्रदान करता है; कुशल, पारदर्शी और बाधा मुक्त अंतर-राज्य और इंट्रा-स्टेट व्यापार एवं किसानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों के कृषि उपज को मार्केट नियामकों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या डीम्ड बाजारों के बाहर; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधा प्रदान करने के लिए और जुड़े हुए मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए। - प्रस्तावना "किसानों का व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020" (2020 की संख्या 10) को 5/6/2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया।

सबसे पहले, कुछ तथ्य।

- एनएसएसओ (NSSO) डेटा के अनुसार भारत में कृषि उपज के विक्रय योग्य अधिशेष का सबसे बड़ा हिस्सा विनियमित बाजार यार्ड स्थानों के बाहर बेचा जाता है। केवल 40% या उससे कम किसान ही विक्रय के लिए मंडियों (विनियमित बाजारों) में जाते हैं।

- भारत में 14 करोड़ कृषि परिवारों के लिए विनियमित बाजारों की संख्या 6700 से भी कम है जिनमें 2284 एपीएमसी हैं जो 2339 प्रमुख बाजार और 4276 उप-बाजार यार्ड संचालित करते हैं। 23000 ग्रामीण हाट भी हैं जो निश्चित दिनों में साप्ताहिक बाजार के रूप में कार्य करते हैं।

- छोटे और सीमांत धारकों के पास विक्रय योग्य अधिशेष काफी कम है और संस्थागत ऋण कवरेज की कमी के चलते, ये किसान स्थानीय व्यापारियों को अपना उपज बेच देते हैं जो अक्सर बीज और कृषि-रसायनों के लिए इनपुट डीलर का काम करते हैं।

- विक्रय चैनलों में एक विविधता मौजूद हैं जो किसानों के लिए संभव हैं; हालांकि, उनमें से सभी को आवश्यक बल और हस्तक्षेप नहीं मिला। इनमें एपीएमसी बाजार और लाइसेंस प्राप्त व्यापारी और कमीशन एजेंट शामिल हैं, राज्य खरीद एजेंसियां जो कुछ राज्यों में महिलाओं के सहायता समूहों और उनके संघों के माध्यम से काम करती हैं, फार्मगेट व्यापारियों, प्रोसेसर (गन्ना या चावल मिलों या कपास मिलों या कताई मिलों के मामले में चीनी मिलों की तरह), इनपुट डीलर / साहूकार, ग्रामीण हाट, उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष विपणन रैतु बाज़ार (rythu bazaars) / उझावार संधाई (uzhavar santhai) / अपनी मंडी (apani mandi)आदि के माध्यम से, सहकारी समितियों और नए FPOs, खुदरा विक्रेताओं, अनुबंध संस्थाओं आदि के लिए प्रत्यक्ष विक्रय, आदि शामिल है।

- ई-एनएएम पोर्टल में मार्च 2019 तक 1.55 करोड़ किसान / विक्रेता, 68000+ कमीशन एजेंट और 1.22+ लाख व्यापारी / खरीदार पंजीकृत थे, जिनमें 650+ एफपीसी / एफपीओ शामिल थे। हालांकि, इस पोर्टल के माध्यम से अंतर-राज्य व्यापार पूरी तरह से कम हो गया है, और इस चैनल में एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) हमेशा किसानों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं।

- नए युग के एफपीओ (किसान निर्माता संगठन) की संख्या जो वास्तव में अपने सदस्यों के लिए काम करती है, एक प्रतियोगी आंकड़ा है और यह संख्या आमतौर पर दर्शाती गई संख्या से काफी कम प्रतीत होती है, जो कि छह हजार है।

पीआर अंकन की कानूनी वास्तविकता और फैक्ट-चेक:

कोरोना महामारी का बहाना बना के तथाकथित "ऐतिहासिक" कृषि सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में भारत में संघीय राजनीति को अनदेखा करके भारत सरकार ने भारतीय कृषि बाज़ार के वैधानिक ढांचे के संचालन में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। कृषि बाजार विक्रय पर एपीएमसी की कथित एकाधिकार में सुधार करने वाले अध्यादेश को 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020' कहा गया है। इसे उस सुधार के रूप में दर्शाया गया है जो किसानों को अपने उत्पाद देश में कहीं भी बेचने की आजादी देगा जबकि इस तथ्य के बारे में आसानी से झूठ बोला जा रहा है क्योंकि किसान पहले से ही कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं - सभी एपीएमसी अधिनियमों में किसानों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखने या छूट देने का प्रावधान था। वे कभी भी किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी नहीं थे और उन्हें वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकने की स्वतंत्रता थी।

वर्तमान सुधारों के पैरोकार बताते हैं कि व्यापारियों पर प्रतिबंध साथ साथ में किसानों पर भी प्रतिबंध है। हालांकि यह कानूनी या व्यावहारिक रूप से सच नहीं है। एपीएमसी अधिनियमों में किसानों को दिए गए छूट के अलावा, कुछ एपीएमसी अधिनियम खरीदारों के लिए टर्नओवर-आधारित छूट की भी अनुमति देते हैं।

यह दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है कि किसान दूसरे राज्यों में अपने सामानों को बेचने जाने के लिए इन सुधारों की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो भी अपने छोटे एवं लघु उत्पादों के साथ दूर के बाजारों में एक जानकारी के साथ बेचने के लिए, और यह कि यह ऐतिहासिक सुधार अब इसकी अनुमति देता है।

इसलिए, हमें इसे सबसे पहले और महत्वपूर्ण तरीके से बाहर लाना चाहिए कि किसानों के बेचने की आजादी, कभी भी सवाल में नहीं थी और पीआर स्पिन के लिए इसे तैयार करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि यह वास्तविक हस्तक्षेप को समझने में कठिन बना देता है।

क्या मंडियाँ कभी भी अधिकांश किसानों के लिए मुख्य विक्रय का केंद्र थी?

एनएसएसओ के आंकड़ों और साथ-साथ देश में विनियमित बाजारों में आवक और व्यापार के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि औसतन 35% किसानों के लिए ही मीडिया विक्रय केंद्र के रूप में एक अच्छी सुविधा प्रदान करती है और वो भी कमोडिटी के आधार पर। जोकि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विनियमन के निर्धारित क्षेत्रों से बाहर के चैनलों में बहुत अधिक व्यापार हो रहा था जिसे अपराधीकृत किया गया था।

यह याद रखना चाहिए कि इस नियम को एक कारण के लिए लाया गया था। मूल्य निर्धारण, वास्तविक भुगतान, ग्रेडिंग संबंधित शोषण, प्रक्रियात्मक और लेन-देन से संबंधित अस्पष्टता, वजन में धोखेबाजी आदि से संबंधित शोषण, इत्यादि किसानों के वास्तविक अनुभव हैं, और कई नियमों के बावजूद इन्हें सुधारा गया।

व्यापारियों / एकाधिकारीयों (जमाखोरों) का सर्टिफिकेशन एवं असली 'प्रतिस्पर्धात्मकता 'की कमी, कमीशन एजेंटों की संदिग्ध भूमिका जो मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए नकदी प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और जो अक्सर लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के परिवार के सदस्य होते हैं (जिनकी फीस को वर्षों से छले जा रहे किसानों के अलावा खरीददार पर एक बोझ बना दिया गया है), विनियमन / APMC के संस्थानों का राजनीतिकरण जो देश में चुनावी राजनीति के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में कार्य करता है, मार्केट यार्ड की पर्याप्त संख्या में कमी या मंडियों में आवश्यक बुनियादी ढांचों की कमी, विनियमित बाजारों में पारिश्रमिक मूल्यों की कमी जहां एमएसपी को भी एक मॉडल मूल्य के रूप में नहीं जाना जाता, सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। इससे यह स्पष्ट है कि कृषि-आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े बड़े व्यापारी किसानों से सीधी खरीद के चलते होने वाले लेन - देन की लागत का वहन न करके किसी भी कीमत पर कई छोटे बिचौलियों/जमाखोरों का सहारा ही लेंगे।

यह कहा जा सकता है कि मंडियों के कामकाज के कई क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है और इस चैनल की अनदेखी करके किसानों के हितों की सेवा नहीं की जा सकेगी। हमें एपीएमसी के अनुसूचित क्षेत्रों और उपयोगी वस्तुओं में पूर्ण नियंत्रण के बिना, मंडियों के कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। हमें मंडियों में कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की आवश्यकता है। हमें एपीएमसी लेनदेन में मध्यस्थता लागत को कम करने की आवश्यकता है। एपीएमसी का अ-राजनैतिकरण करके उसे मुख्य रूप से संबंधित लाइन विभाग द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। यह कोई रहस्य नहीं है कि विनियमित बाजारों ने भी किसानों द्वारा एमएसपी की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की है। नीलामी के लिए किसी भी वस्तु का आधार मूल्य घोषित MSPs से ज्यादा होनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो व्यापारियों के लिए एक कम-भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए। यदि व्यापारी नहीं तो किसानों-विक्रेताओं को उचित मूल्य से कम-भुगतान प्रणाली की आवश्यकता है। उपरोक्त के अनुसार संशोधन और निवेश लाभ पहुंचाएंगे।
बिहार और केरल, जहां कोई एपीएमसी नहीं है और कृषि बाजारों को अ-विनियमित किया है, के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि किसानों को ऐसी प्रणाली में कोई लाभ नहीं हुआ है।

बाजार हस्तक्षेप एवं अधिग्रहण:

राज्य की खरीद एजेंसियों की खरीद की कार्रवाई शुरू करने और बाजार की कीमतों को बढ़ावा देने की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है। इस बात पर निश्चित रूप से जोर नहीं दी जा रही है कि राज्य को सभी किसानों की सभी कृषि उपज की खरीद करनी चाहिए। यहां जो वकालत की जा रही है, वह स्मार्ट और त्वरित हस्तक्षेप संचालन का है जो किसानों के खातिर बाजार की कम कीमतों का ख्याल रखता है, ताकि अन्य खरीदार भी सरकारी हस्तक्षेप के कारण कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर हों। यह काम सीजन के अंत में किसानों से बड़ी आवक के समय खुले बाजारों में खरीदी गई सामग्री को डंप किए बिना किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, कोविड -19 के समय जब लॉकडाउन ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया, जिनके जीवन को "रोज कमाना रोज खाना" के रूप में वर्णित किया जा सकता है, के परिवारों के लिए "खाद्य सुरक्षा" सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पीडीएस प्रणाली को खाद्यानों की विविधता के साथ-साथ मात्रा के हिसाब से भी विस्तारित किया जाए। खाद्य योजनाओं के लिए खरीद हमेशा एमएसपी पर होती है, और इसमें स्थानीय सीबीओ (सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ आदि) को जमीनी स्तर पर और स्थानीयकृत खरीद कार्यों के लिए शामिल किया जाए।

अनदेखा किए गए प्रस्ताव - यह उदासीनता और उपेक्षा किसानों की मदद नहीं करता:

एनडीए शासन में भारत सरकार ने दिखाया है कि कैसे डिजाइन और कार्यान्वयन मुद्दों को गंभीरता से सम्बोधित ना करके, अपने पी आर स्टंट को गंभीर और स्थिर हस्तक्षेपों की तुलना में अधिक महत्व दिया और एक योजना से दूसरे योजना, एक घोषणा से दूसरी घोषणा करती रही है। उदाहरण के लिए यह PM-AASHA स्कीम पर लागू होता है। धूमधाम से घोषित किए गए योजना पर कोई निवेश नहीं किया गया। नए एमएसपी पर खरीद के लिए कोई निवेश नहीं किया गया है, जो सरकार के अनुसार उत्पादन की लागत से 50% अधिक है जो कि निश्चित रूप से सत्य नहीं है। जबकि 2000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ ग्रामीण हाटों को सुधारने के लिए GRAM योजना की घोषणा की गई थी जिसमें बहुत ही कम क्रियान्वयन देखा गया था। आखिरी जानकारी के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत 150 हाट को भी अपग्रेड नहीं किया गया। रायथू बाज़ारों की अवधारणा को सभी राज्यों में नहीं बढ़ाया गया था। 10,000 एफपीओ के समर्थन के बारे में घोषणा की गई लेकिन किसानों के साथ जमीन पर बहुत कम अनुभव वाले एक निजी सलाहकार को इसका कार्यान्वयन सौंपा गया जिससे यह स्पष्ट है कि एक और योजना के क्रियान्वयन की बलि दी जा रही है।

वर्तमान अध्यादेश:

वर्तमान अध्यादेश खरीददारों को किसानों या अन्य व्यापारियों से "किसानों की उपज" की (ए पी एम सी के द्वारा संचालित/विनियमित स्थानों के बाहर) खेत-द्वार, फैक्टरी परिसर, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और अन्य स्थानों सहित किसी भी "व्यापार क्षेत्र" में खरीद की की अनुमति देता है । अजीब तरह से, व्यापारी के परिभाषा में अन्तिम - उपयोगकर्ता या उपभोक्ता को भी शामिल करता है!

यह अध्यादेश "किसानों की उपज" और "अनुसूचित किसानों की उपज" को निर्दिष्ट करता है। अनुसूचित किसानों की उपज के निर्दिष्ट उत्पादन में किसी भी राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत विनिमय किया जा सकता है। अनुसूचित किसानों की उपज के लिए - केवल उन व्यापारियों को जिनके पास आईटी अधिनियम या ऐसे अन्य दस्तावेज के तहत आवंटित पैन नंबर है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, वे ही सिर्फ कारोबार कर सकते हैं। इसके अलावा, 'अनुसूचित किसानों की उपज' का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रणाली में पंजीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है और व्यापार लेनदेन के तौर-तरीकों का अनुपालन और भुगतान के तरीके जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है को मानना होगा।

अनुसूचित किसानों की उपज के लिए, यह अध्यादेश निर्दिष्ट करता है कि किसानों को उसी दिन भुगतान किया जाना चाहिए, या डिलीवरी की रसीद के साथ अधिकतम तीन कार्यदिवसों के भीतर, जिसमें उसी दिन किसान को दी जा रही देय भुगतान राशि का उल्लेख किया गया हो।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "किसानों की उपज" के लिए इस प्रकार का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि "अनियत" किसानों की उपज बेचने वाले किसानों को संरक्षित क्यों नहीं किया जाएगा।

हो सकता है कि अध्यादेश में पंजीकरण आवश्यकताओं और कुछ लेनदेन के तौर-तरीकों के अनुपालन के लिए वैधानिक किया का सकेगा परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कौन व्यापार लेनदेन की निगरानी करेगा या देखेगा या कम से कम इसमें शामिल लोगों की गणना कर सकेगा।

लाइसेंसिंग प्रणाली के बिना, कम से कम खरीदारों के डेटाबेस के लिए राज्यों में एकीकृत पंजीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। हालाँकि, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक असमान बाजार व्यवस्था में, जहां अधिकांश किसान अपनी काटी गई उपज को बेचने के लिए बेताब होते है, ताकि नकदी का जुगाड किया जा सके, जिसमें कर्ज लेना और देना भी शामिल है, क्या वे एक दिवस भुगतान पर जोर दे पाएगा? या डिलीवरी और भुगतान कारण दस्तावेज-आधारित प्रमाण पर जोर दे पायेगा? या क्या वे पूरी तरह से नए खरीदारों को खोजने में सक्षम होंगे जिसपे वे भरोसा कर सकते हैं और अपनी उपज दे सकते हैं?

विवाद समाधान:

जून 2020 के अध्यादेश में, विवाद समाधान तंत्र को सरल अथवा ज्यादा सरल रखा गया है! अध्यादेश यह परिकल्पना करता है कि राशि की वसूली और जुर्माना लगाना, 3 या 5 सदस्यीय सुलह बोर्ड द्वारा संभव होगा, जिसमें अध्यक्ष और दोनों पक्षों (किसान और व्यापारी) के बराबर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह तथ्य कि यह एक किसान और व्यापारी तक सीमित है, यह उन सभी व्यापारिक विवादों की तुलना में अधिक प्रबंधनीय है, जिनमें व्यापारियों के बीच होने वाले विवादों को भी शामिल होने की अनुमति दी गई है। 30-दिन की समय-सीमा के साथ एसडीएम के नेतृत्व वाले इस विवाद समाधान प्राधिकार के लिए या कोई अन्य (व्यापारी को व्यापार करने से रोकने के अतिरिक्त शक्ति के साथ) एक अपील प्राधिकार जिनमें कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल होंगे जिन्हे फिर से 30 दिन के अंदर मामलें को सुलझाना होगा, इतने ज्यादा अपील को सुलझा पाएंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि, किसान के निवास स्थान पर या जहां व्यापार लेनदेन हुआ था (जहां राज्यों द्वारा, जैसा कि अधिवक्ताओं द्वारा पेश किया जाएगा) विवाद समाधान आवेदन कहां किया जायेगा? किस प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्यों की आवश्यकता होगी जब असमान शक्ति संबंधों के परिणामस्वरूप किसान के पास लेनदेन का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं उपलब्ध होगा है? ये सभी विवरण, नियमों पर छोड़ दिया गया है और प्रतीक्षित है।

समीक्षात्मक ऐसा प्रतीत होता है कि किसान के साथ न्याय, किसानों को पैसों के भुगतान के रूप में समझा जाता है जो किसान और व्यापारियों के बीच के शक्ति संबंधों पर आधारित होता है। यह प्रतीत होता है कि न्याय, उदाहरण के लिए किसी भी अनुचित वजन या खरीददार द्वारा अनुचित ग्रेडिंग या अनुचित रूप से कम कीमत तय करने इत्यादि, के बारे में नहीं है।

राज्य सरकारें, उनका राजस्व और भूमिकाएं:

अध्यादेश की संवैधानिक औचित्य पर बहस हो रही है। यह राज्य का विषय है या समवर्ती विषय है इसकी वैधता की बात नहीं है बल्कि संघीय राजनीति के भावना के बारे में भी है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 26 में राज्य लिस्ट के तहत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में है लेकिन यह लिस्ट III (समवर्ती लिस्ट) की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन है। इसी प्रकार, राज्य लिस्ट की प्रविष्टि 27, लिस्ट III के प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के बारे में है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33, व्यापार और वाणिज्य में, और उत्पादन, औद्योगिक उत्पादों का आपूर्ति और वितरण, खाद्य तिलहन और तेल सहित खाद्य सामग्री, मवेशियों के चारे, कच्चे कपास और कपास के बीज और कच्चे जूट, के बारे में है। यहाँ, संसद द्वारा पारित कानून प्रबल होगा और न कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून यदि

यह संसद के द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के विरूद्ध है। इसके अनुसार यह स्पष्ट है कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 सभी प्रकार के "किसानों के उत्पादन" को कवर नहीं करती है। पंजाब सरकार तर्क दे रही है कि यह वास्तव में औद्योगिक वस्तुओं और उद्योग के लिए कृषि आधारित कच्चे माल के बारे में है।
यह भी स्पष्ट है कि अंतर्राज्यीय ट्रेडिंग राज्य सरकारों के दायरे में है अब केंद्र सरकार ने इसको हड़प लिया है। इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता शायद न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाएगी जब इस अध्यादेश को राज्य सरकारों जैसे पंजाब द्वारा चुनौती दी जाएगी। उदाहरण के लिए पंजाब, वर्तमान अध्यादेश के कारण महत्वपूर्ण राजस्व खो रहा है क्योंकि अध्यादेश में कहा गया है कि अनुसूचित किसानों की उपज में व्यापार और वाणिज्य के लिए एक व्यापार क्षेत्र में किसी भी किसान या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेनदेन मंच पर कोई बाजार शुल्क या उपकर या अधिकर नहीं लगाया जाएगा। अगर पंजाब में व्यापार एपीएमसी द्वारा विनियमित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर के "व्यापार क्षेत्रों" में चला जाता है, तो उससे राज्य सरकार का राजस्व प्रभावित होगा। दूसरी ओर, यदि खरीद एजेंसियां एपीएमसी के क्षेत्राधिकार के अधीन मंडियों के बुनियादी ढांचे से काम करना जारी रखती है।

अध्यादेश की धारा 14 यह कहती है अध्यादेश में लिखित प्रावधान अन्य अधिनियमों पर प्रबल होंगे। क्या इसका मतलब यह है कि निरस्त होने की आवश्यकता के बिना राज्य एपीएमसी अधिनियम बने रहेंगे। इस बीच, जब हम इस अध्यादेश पर बहस कर रहे हैं, कई राज्यों ने पहले से ही अपने राज्यों में एपीएमसी नियमों को बदलने के लिए और कृषि उपज व्यापार को विनियमित करने के लिए विभिन्न तरीकों से अपने स्वयं के अध्यादेशों का उपयोग किया है।

इसके अलावा, एक अन्य विश्लेषक ने भारतीय किसानों की गहरी संरचनात्मक बाधाओं को देखते हुए बताया है कि इस तरह के कानूनी सुधारों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित होने की संभावना नहीं है। वह बताती हैं कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए आम सहमति, समन्वय और क्षमता की बहुत आवश्यकता है। तथा इसे राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल किए बिना हल नहीं किया जा सकता है। वर्तमान अध्यादेश वास्तव में राज्य सरकारों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है!

किसानों के लिए सतह रेखा

अंत में, किसानों के लिए बाजार की बात नहीं बल्कि कीमत की बात है।

उपज की कीमतों में पारिश्रमिक के साथ -साथ उत्पादन की लागत और गरिमापूर्ण जीवनयापन के लिए जो एक मुनाफा छोड़ सके सम्मिलित होना चाहिए (यही कारण है कि किसान आयोग के व्यापक सी 2 + 50% के फार्मूले की मांग एमएसपी, किसानों के साथ प्रतीत होती है)। विनियमित बाजारों में भी, किसानों को पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिलता। न ही उन्हें अ-विनियमित बाजारों में ऐसी कीमतें मिलती है। न ही ई-एनएएम (e-NAM) में। तथ्य यह है कि बहुसंख्यक छोटे किसानों के लिए बाजार और कीमतें क्रेडिट के साथ बंधी हुई हैं, छोटे संस्करणों के साथ, कटाई के बाद तत्काल रिटर्न की तीव्र आवश्यकता और एकत्रीकरण के द्वारा लाभ का अभाव कोई भी एक उपाय से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। और उक्त अध्यादेश निश्चित रूप से कोई चांदी की गोली नहीं है, हालांकि यह किसानों की उपज के विक्रय के लिए और भी रास्ते खोल सकता है। तथापि, इन उपायों पर किसानों के लिए एक सोच विचार और संरक्षक उपायों की जरूरत है। इसे देखते हुए की ऐसे उपाय अभी एक असंतुलित पर्यावरण पैदा करेंगे जहां एक अकेले किसान को पूरे बाजार के सामने खड़ा होना होगा।

किसानों के लिए पारिश्रमिक मूल्यों की महत्वपूर्णता को महसूस करते हुए, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC), जिसकी लेखक एक हिस्सा है, ने सभी किसानों को पारिश्रमिक मूल्य की गारंटी देने के लिए एक सांविधिक रूपरेखा तैयार की है। यह महत्वपूर्ण समय है कि सरकारें देश के सभी किसानों को कानूनी अधिकार प्रदान करने की सोचें। इस तरह के कानून को किसानों के अधिकार के रूप में पारिश्रमिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कृषि कमोडिटीज बिल, 2018 रूप में लागू करें।

कविता कुरुगंटी, एलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (ASHA, www.kisanswaraj.in) से जुड़ी एक किसान अधिकार कार्यकर्ता और कृषि नीति विश्लेषक हैं । कविता भारत में प्रमुख किसान आंदोलनों के साथ मिलकर काम करती है।